आकाशवाणी शिमला
09.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री ने कहा–राज्य सरकार हिमकेयर योजना में करेगी सुधार जबकि सहारा योजना से अपात्र होंगे बाहर।
- उप–मुख्यमंत्री ने कहा–जल शक्ति विभाग में अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन से बाहर काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
- प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर विधानसभा में मंथन शुरू–नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खस्ताहाल वित्तीय स्थिति के लिए सुक्खू सरकार को ठहराया जिम्मेदार।
- केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल में 92 हजार 3 सौ से अधिक घरों को दी मंजूरी।

प्रश्नकाल

प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना में सुधार और सहारा योजना को और मजबूत करेगी ताकि पात्र असहाय लोगों को इन योजनाओं का वास्तव में लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में दखल देते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना में गड़बड़ियों, खासकर निजी अस्पतालों को पहुंचाए जा रहे लाभ की शिकायतों के बाद सरकार ने इस योजना में सुधार का निर्णय लिया है। इसी के तहत सरकार ने निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत इलाज की सुविधा को वापस ले लिया है और कर्मचारियों को भी हिमकेयर योजना के तहत इलाज की सुविधा से बाहर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया पूर्व सरकार ने राज्य के एक सौ 37 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को हिमकेयर योजना के तहत इलाज के लिए इंपैनल्ड किया था ताकि उन्हें अधिक पैसा दिया जा सके।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर योजना की 3 सौ 55 करोड़ रुपए की देनदारियां अभी भी लंबित हैं। इनमें से एक सौ 27 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां निजी स्वास्थ्य संस्थानों की हैं, जबकि 2 सौ 27 करोड़ रुपए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी, टांडा और पीजीआई के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना में हुई गड़बड़ियों की कैबिनेट की सब कमेटी जांच कर रही है और सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ियां सिर्फ हिमकेयर योजना में ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना में भी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सहारा योजना को और मजबूत करेगी और अपात्र लोगों को इससे बाहर किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आईजीएमसी और टांडा में बड़े पैमाने पर डाक्टरों और नर्सों की भर्तियां करने जा रही हैं। इसके तहत 2 सौ डॉक्टरों की भर्ती के लिए लोकसेवा आयोग को सिफारिश भी भेज दी गई है और नियमित भर्तियां होने तक इन दोनों संस्थानों में डॉक्टरों व नर्सों की आउटसोर्स आधार पर भर्तियां की जाएंगी। इससे पूर्व, मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में सहारा योजना के तहत 16 हजार 7 सौ 98 आवेदन आए थे।

इनमें से 11 हजार 4 सौ 19 को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 5 हजार 3 सौ 79 अभी लंबित हैं। इसी तरह हिमकेयर योजना के तहत 2 लाख 45 हजार एक सौ 41 आवेदन आए थे, जिनमें से 2 लाख 43 हजार 6 सौ 14 आवेदनों को मंजूर कर लिया गया है, जबकि एक हजार 5 सौ 17 आवेदन लंबित हैं। विधायक सुखराम चौधरी की अनुपस्थिति में विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड की योजना में विधानसभा क्षेत्र की लिमिट एक सौ 75 करोड़ तय है। इसमें सरकार ने 20 करोड़ बढ़ाकर एक सौ 95 करोड़ किया है। इसमें विधायक इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक सौ 75 करोड़ रुपए की परिधि में स्कीमें आएगी, तो उसे स्वीकृति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के तहत शिमला शहरी हलकों में ही सड़कें नहीं बन रही है, क्योंकि यह शहरी क्षेत्र है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक अप्रैल 2022 से लेकर 31 जुलाई तक नाबार्ड के तहत प्रदेश में 3 सौ 50 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान नाबार्ड के पास कुल 3 सौ 18 योजनाएं विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर रही है।

नियम–62

प्रदेश में जल शक्ति विभाग में अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन से बाहर जाकर काम करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में विधायक पवन काजल द्वारा नियम 62 के तहत कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के कारण हो रही असुविधाओं को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि विभाग के जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डंगे लगाए हैं, सड़कें बनाई हैं और शमशान घाटों का निर्माण किया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि जरूरी हुआ तो इन कार्यों का पैसा संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा। अग्निहोत्री ने विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाए गए ऐसे सभी कार्यों का भुगतान रोकने की भी घोषणा की।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

इस बीच नियम–62 के तहत ही विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा जिया–बड़सर घनेता की सिंचाई योजना कथुल्ल कुहल की पाईपें फट जाने पर सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट चला रहे पूंजीपति या उद्यमी प्रदेश के लोगों को पानी से वंचित नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में कूहलों को बचाने के लिए सरकार व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी और इस कथुल्ल कुहल योजना में समस्या को दूर करने के लिए उपायुक्त और विभाग के अधिकारियों को इस स्थान का दौरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक विपिन सिंह परमार ने जिस कुहल का जिक्र किया है, उसकी मरम्मत के लिए 45 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है।

वित्तीय स्थिति

भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विधानसभा में आज नियम–130 के तहत मंथन आरंभ हुआ। चर्चा के पहले दिन विपक्ष ने सरकार को वित्तीय संकट के मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस आर्थिक संकट के समाधान की जिम्मेदारी भी सरकार की है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति की हालत यह है कि विकास के लिए सिर्फ 28 फीसदी बजट ही रह गया है, जबकि पूर्व भाजपा की सरकार में 2017–18 में यह 39 दशमलव पांच–छः फीसदी था। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति और राज्य के कर्ज के बोझ तले दब जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जब भाजपा सत्ता में आई तो उसे 48 हजार करोड़ रुपए का ऋण विरासत में मिला। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच सालों में सिर्फ 19 हजार 6 सौ करोड़ रुपए का ऋण लिया, जो राज्य के लिए निर्धारित कर्ज सीमा से बहुत कम था। यही नहीं, भाजपा जब सत्ता छोड़कर गई तो प्रदेश सरकार के पास छह हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की सीमा मौजूद थी।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से निकलने के लिए किसी भी मंदिर का सोना या चांदी गिरवी नहीं रखने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और सरकार लोगों की भावनाओं की कद्र करती है। उन्होंने विपक्ष पर इस तरह की बातें कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चल रही चर्चा में विधायक भवानी सिंह, विपिन सिंह परमार और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी हिस्सा लिया।

अनुराग ठाकुर

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में 92 हज़ार 3 सौ 64 घरों को मंजूरी प्रदान की है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस वर्ष केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर परिवार को पक्का मकान देने की नीति के अंतर्गत देश के अन्य छोटे राज्यों में हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए सबसे ज़्यादा घर मंजूर किए हैं। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लिए ये सौगात प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है।

जयराम

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एकमुश्त 92 हजार 3 सौ मकान देने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हिमाचल को दिया गया ये शानदार तोहफा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने आपदा के मद्देनजर 17 हजार 5 सौ मकान दिए गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश को 92 हजार से अधिक घरों का तोहफा दे रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश की सुक्खू सरकार सीमेंट के दाम बढ़ाकर गरीबों के लिए घर बनाने के सपने को मुश्किल कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक सप्ताह में 2 बार सीमेंट के दाम में वृद्धि

सुक्खू सरकार की नाकामी है और जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से सीमेंट के दामों में सौ रूपए से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है।

नुकसान

किन्नौर जिला के पांगी गांव की पीरी ढांक से आज सुबह चट्टानें गिरने से सेब बागीचों सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अचानक पहाड़ी दरकने से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है और अभी भी बीच–बीच में पत्थर गिरने का क्रम जारी है। पहाड़ी दरकने से पांगी गांव की 25 बीघा जमीन पर फैले 60 बागवानों के सेब बागीचों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा चार दोगरियां भी पत्थरों की चपेट में आने क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राजस्व विभाग को नुकसान का आकलने करने का निर्देश दिए हैं और स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में न जाने आग्रह किया है।